(b) and (c) Madhya Pradesh has been complaining that it is not receiving its share of water from Rajasthan during the time of peak Rabi demand due to excessive drawal by Rajasthan, in the upper reaches of the canal. But according to Rajasthan, Madhya Pradesh has been abstracting water upstream of Gandhisagar Dam, thereby reducing the inflows into the reservoir. However, except in one year as above, Madhya Pradesh has been getting more flows.

(d) Yes, Sir.

(e) It is for the two State Governments to take a decision in the matter.

Production capacity of steel plants of SAIL

816. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the total production capacity of all the plants of Steel Authority of India Limited as on 31st March, 1986; and

(b) what was the total actual production of the said plants during last year?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) The total production capacity of saleable steel of all the steel plants of Steel Authority of India Limited (including IISCO) as on 31st March, 1986 was 7.2 million tonnes per annum.

(b) The total production of saleable steel of these plants in 1985-86 was 6.00 million tonnes. This production was 14 per cent more than in 1984-85.

कीटनाशक दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाएं

817. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों अथवा क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन प्रयोगशालाओं को स्थापित करते समय मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी एक प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) राज्यों में जहां कहीं कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं वे सब राज्य सरकारों द्वारा ही स्थापित की गई है । कीटनाशी अधिनियम की सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने फरीदाबाद (हरियाणा) में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थापित की है, जिसका एक यूनिट बम्बई (महाराष्ट्र) और दूसरा यूनिट हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिये पांच क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिये पहले ही योजना को मंजूरी दे दी है ।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय प्रयोगशालायें जिन स्वीकृत स्थानों तथा राज्यों/संघ

राज्यक्षेत्रों की जरूरतें पूरी करेगी वे नीचे दिये गये हैं :—

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान
उत्तरी	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एवं चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र	चण्डीगढ़
पश्चिमी	गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र	बम्बई
केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार	कानपुर
दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांण्डचेरी और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र	हैदराबाद
पूर्वी	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।	कलकत्ता

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की क्षेत्रीय कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशाला मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी।

Request of Andhra Pradesh for utilisation of funds earmarked for special nutrition programme

818. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Government of Andhra Pradesh asked the Central Government for reconsidering and approving the utilisation of the Special Nutrition Programme Funds released to the State Government on 28th February, 1985;

(b) if so, what was the amount involved; and

(c) what action has been taken by the Central Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Andhra Pradesh have requested for Government of India's approval for diverting Rs. 62.28 lakhs sanctioned for special nutrition programmes in the wake of cyclone/floods of 1984 towards construction of Anganwadi centres.

(c) The request of the State Government has not been acceded to. The central assistance specifically earmarked for an item like special nutrition programme which aims at providing succour to poorer section of society cannot be allowed to be diverted. The High Level Committee on Relief while considering the matter of inter-sectoral diversion also opined that such diversions should not be allowed as it would amount to deviating from the established principles.

अहाता किदारा, दिल्ली में बसे परिवारों को पट्टे

819. **श्री अच्छे लाल बाल्मीक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र टी-क्वाटर्स अहाता